RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 24 से 30 जनवरी 2026 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 13 | अंक-76 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

भारत-यूरोपीय संघ FTA से पहले चरण में 5 अरब डॉलर निर्यात का अवसर

व्यापार समझौते से टैरिफ में 90% कटौती, ऑटो, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा; 2030 तक 100 अरब डॉलर द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के शुरुआती चरण में ही 5 अरब डॉलर का अतिरिक्त निर्यात अवसर खुल सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि समझौते से टैरिफ में 90% से अधिक कटौती होगी, जिससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा।

यह अनुमान EU के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच आया है, जहां भारत ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कटौती की मांग कर रहा है। EU ने भी मोटरसाइकिल, रसायन, मशीनरी और वाइन जैसे उत्पादों पर छूट मांगी है। समझौते से भारत का EU के साथ व्यापार घाटा कम होगा, जो वर्तमान में 50 अरब डॉलर से अधिक है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऑटो सेक्टर में 2 अरब डॉलर, फार्मा में 1.5 अरब डॉलर और टेक्सटाइल में 1 अरब डॉलर का अतिरिक्त निर्यात संभव है। EU भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जहां 2025 में निर्यात 80 अरब डॉलर पार कर गया। FTA से भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यूरोपीय बाजार में ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी।

मंत्रालय के अनुसार, समझौता 2026 के अंत तक अंतिम रूप ले सकता है। यह 'विकसित भारत 2047' विजन से जुड़ा है, जहां भारत 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि कृषि और डेयरी सेक्टर में EU की मांग से छोटे किसानों को चुनौती मिल सकती है। फिर भी, यह FTA भारत की वैश्विक व्यापार में स्थिति को मजबूत करेगा।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करें; 500 अरब डॉलर का अवसर: पीएम मोदी

नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन और ग्रिड में बड़े निवेश की अपील; 2030 तक 500 GW नॉन-फॉसिल लक्ष्य, आत्मनिर्भर ऊर्जा का रोडमैप

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत का ऊर्जा सेक्टर 500 अरब डॉलर (लगभग 42 लाख करोड़ रुपये) का निवेश अवसर प्रदान कर रहा है। यह बात उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में कही, जहां उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा यात्रा और आत्मनिर्भरता के विजन को रेखांकित किया।

पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया का सबसे तेज बढ़ता अर्थव्यवस्था है और ऊर्जा इस विकास का आधार है। हम 2030 तक 500 गीगावाट नॉन-फॉसिल ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखते हैं। सौर, विंड, हाइड्रोजन, बायोएनर्जी और ग्रिड इंफ्रा में भारी संभावनाएं हैं। उन्होंने जोर दिया कि भारत में ऊर्जा मांग अगले दशक में दोगुनी हो जाएगी, और यह निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर है।

प्रधानमंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, PLI स्कीम और रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स जैसे कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में वैश्विक लीडर बनने की राह पर है। हमारी नीतियां निवेशकों के लिए अनुकूल हैं टैक्स छूट, आसान लैंड और तेज अप्रूवल, उन्होंने कहा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह अपील FDI को गति देगी, जो 2025 में ऊर्जा सेक्टर में 15 अरब डॉलर से अधिक आई थी। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो है, और इसके लिए 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, "भारत में निवेश न केवल लाभ देगा, बल्कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में योगदान भी देगा।

यह घोषणा भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास के विजन को मजबूत करती है। वैश्विक निवेशकों के लिए भारत अब सबसे आकर्षक ऊर्जा बाजार बन रहा है।

EV मार्केट में BYD का दबदबा! भारत में मांग इतनी तेज कि कंपनी विस्तार पर विचार कर रही

इलेक्ट्रिक कारों की बुकिंग में उछाल, कंपनी ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने की योजना बनाई; टाटा और महिंद्रा को चुनौती

नई दिल्ली: चीनी इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज BYD भारत में बड़े पैमाने पर विस्तार की तैयारी कर रही है। कंपनी के भारत प्रमुख ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों कारों की बुकिंग जमा हो चुकी है, जो भारतीय बाजार में BYD की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। Atto 3 और Seal जैसे मॉडल्स की मांग इतनी तेज है कि डिलीवरी में 6-9 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

BYD ने कहा कि वह भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर विचार कर रही है। कंपनी पहले से ही चेन्नई में असेंबली यूनिट चला रही है, लेकिन अब फुल-स्केल प्रोडक्शन प्लांट लगाने की योजना है। यह कदम 'मेक इन इंडिया' नीति के अनुरूप होगा और आयात शुल्क (वर्तमान में 70-100%) से बचत करेगा। साथ ही, कंपनी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार कर रही है, ताकि ग्राहकों को रेंज और चार्जिंग की चिंता कम हो।

भारतीय EV बाजार में BYD टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियों को चुनौती दे रही है। Atto 3 की कीमत 33-35 लाख रुपये है, जो प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत स्थिति रखती है। कंपनी का दावा है कि भारत में EV अपनाने की दर 2026 में 10% पार कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि BYD का विस्तार भारत को EV हब बनाने में मदद करेगा। हालांकि, अमेरिकी-चीन तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बीच कंपनी को सावधानी बरतनी होगी। BYD ने कहा कि वह भारतीय नियमों का पूरी तरह पालन करेगी। यह कदम भारतीय EV बाजार में नई प्रतिस्पर्धा लाएगा और उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प देगा।

Radisson Hotel Group Targets India's Booming Rs 1.34 trillion Spiritual Tourism Market with Four New Launches

New Properties in Varanasi, Ayodhya, Haridwar, and Tirupati to Cater to Rising Demand for Faith-Based Travel; Aims to Capture Growing Pilgrim and Wellness Segments

New Delhi: Radisson Hotel Group has announced an aggressive expansion into India's fast-growing spiritual tourism market, valued at Rs 1.34 trillion, with the launch of four new hotels strategically located in key pilgrimage destinations. The properties Radisson Blu in Varanasi, Radisson in Ayodhya, Radisson in Haridwar, and Radisson in Tirupati will cater to the increasing number of domestic and international pilgrims seeking comfortable, modern accommodation near sacred sites.

The initiative reflects the surge in spiritual and faith-based travel post-pandemic, with millions visiting sites like Ayodhya's Ram Temple, Varanasi's ghats, Haridwar's Ganga Aarti, and Tirupati's Venkateswara Temple each year. Radisson aims to bridge the gap between traditional pilgrimage and contemporary hospitality by offering wellness-focused amenities, vegetarian dining options, and proximity to religious landmarks.

itual tourism is evolving rapidly, with travellers seeking both devotion and comfort," said Olivier Chavy, President, Radisson Hotel Group for Asia Pacific. These four launches position us to capture a significant share of this high-potential market while supporting sustainable tourism in sacred cities.

The new hotels feature modern rooms, banquet facilities for religious events, and spa services tailored for pilgrims. The Ayodhya and Varanasi properties are already operational, while Haridwar and Tirupati are slated for completion by mid-2026. The group plans further expansion in Rishikesh, Amritsar, and Shirdi.

Industry experts estimate spiritual tourism contributes 10-12% to India's overall tourism revenue, with domestic pilgrim footfall exceeding 500 million annually. The segment has grown 18% YoY, driven by improved infrastructure, digital booking platforms, and rising disposable incomes.

Radisson's strategic entry is expected to intensify competition in the faith-based hospitality space, currently dominated by local chains and heritage properties. Shares of parent company Radisson Hotel Group traded stable on global exchanges, but analysts see strong upside in India's tourism recovery.

As India targets $200 billion in tourism revenue by 2030, Radisson's focus on spiritual destinations underscores the sector's potential to blend faith, wellness, and economic growth.

बजट 2026: फार्मा उद्योग ने मांगे ज्यादा टैक्स क्रेडिट, तेज अप्रूवल और R&D प्रोत्साहन

PLI स्कीम का विस्तार, इनोवेशन और निर्यात बढ़ाने की मांग; 2030 तक 130 अरब डॉलर बाजार का लक्ष्य

नई दिल्ली: ल्बजट 2026 की तैयारियों के बीच फार्मा उद्योग ने सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल्स अलायंस (IPA), OPPI और IDMA जैसे संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने प्री-बजट मीटिंग में कहा कि उच्च टैक्स क्रेडिट, तेज दवा अप्रूवल और R&D पर अधिक प्रोत्साहन से भारत को वैश्विक फार्मा हब बनाया जा सकता है।

उद्योग ने PLI स्कीम का विस्तार करने की मांग की है, ताकि क्रिटिकल APIs, जेनेरिक दवाओं और बायोसिमिलर में निवेश बढ़े। वर्तमान में PLI से 76,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन मिले हैं, लेकिन उद्योग चाहता है कि इसे 1 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाए। साथ ही, R&D पर 200% टैक्स क्रेडिट की मांग की गई है, जो वर्तमान 150% से अधिक होगी।

फार्मा कंपनियों ने CDSCO और DCGI के अप्रूवल प्रक्रिया को तेज करने की अपील की, ताकि नई दवाएं बाजार में जल्दी आएं। निर्यात बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में निवेश की मांग भी रखी गई। OPPI के प्रेसिडेंट ने कहा, 2030 तक भारत का फार्मा बाजार 130 अरब डॉलर का हो सकता है, लेकिन इसके लिए बजट में मजबूत प्रोत्साहन जरूरी है।

उद्योग ने बायोसिमिलर और वैक्सीन सेगमेंट में विशेष पैकेज की मांग की, ताकि वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़े। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मांगें बजट में शामिल होने से दवा की कीमतें नियंत्रित रहेंगी और निर्यात 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह बजट फार्मा सेक्टर के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

Foreign Investors vs Domestic Money: Who Really Controls Indian Markets?

For many years, Indian stock markets were seen as being heavily influenced by foreign investors. Whenever Foreign Institutional Investors (FIIs) bought shares, markets moved up, and when they sold, markets fell. But over the last decade, this picture has changed significantly. Today, a new question is being asked: do foreign investors still control Indian markets, or has domestic money taken charge?

Foreign investors play an important role in Indian markets. They bring large pools of global capital and help improve liquidity and market depth. FIIs are often quick to react to global events such as changes in US interest rates, geopolitical tensions, or currency movements. Because of this, their buying or selling can cause sharp short-term movements in the market. When FIIs invest heavily in India, indices like the Nifty and Sensex usually rise. When they pull out money, volatility increases.

In the past, FII flows were the dominant force. During periods like the global financial crisis of 2008 or the taper tantrum of 2013, heavy foreign selling led to sharp market corrections in India. Domestic investors at that time were not strong enough to absorb these outflows, so markets fell sharply.

However, the situation today is very different. Domestic Institutional Investors (DIIs) mainly mutual funds, insurance companies, pension funds, and retail investors have grown enormously. The rise of Systematic Investment Plans (SIPs) has created a steady and predictable flow of money into the stock market every month. Even during periods of global uncertainty, this domestic money continues to come in, providing strong support to the market.

Retail participation has also increased sharply. Millions of new investors have entered the market through digital platforms and mobile apps. This has broadened the investor base and reduced dependence on foreign capital. During recent years, there have been several occasions when FIIs were net sellers, but Indian markets remained stable or even moved higher because domestic investors stepped in.

A clear example of this shift was seen after the COVID-19 pandemic. In the early months of 2020, foreign investors sold heavily due to global panic. But strong domestic buying, combined with government and central bank support, helped Indian markets recover faster than many global peers. More recently, during periods of global rate hikes and geopolitical stress, domestic funds have often absorbed foreign selling.

So, who really controls Indian markets today? The answer lies in understanding time horizons. Foreign investors still have a strong influence on short-term market movements. Their decisions can cause quick rallies or corrections, especially in large-cap stocks. However, domestic money now plays a much bigger role in setting the long-term trend of the market.

Domestic investors tend to invest with a longer-term view, driven by India's growth story, rising incomes, and expanding middle class. This steady capital acts as a stabilising force, reducing extreme volatility and making the market more resilient to global shocks.

In conclusion, Indian markets are no longer controlled by foreign investors alone. While FIIs continue to matter, domestic money has emerged as the backbone of the market. The growing strength of Indian investors has made the market more balanced and less vulnerable. Today, it is this combination of global capital and strong domestic participation that truly drives Indian stock markets.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति बढ़ाई: कूटनीतिक तनाव के बावजूद ऊर्जा सहयोग जारी

1,600 MW से अधिक आपूर्ति, बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान; भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर

नई दिल्ली: अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है, भले ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ा हो। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि वह बांग्लादेश को अब 1,600 MW से अधिक बिजली सप्लाई कर रही है, जो पहले 1,200 MW थी। यह आपूर्ति झारखंड के गोड्डा पावर प्लांट से की जा रही है, जो विशेष रूप से बांग्लादेश के लिए बनाया गया है।

अडानी पावर के प्रवक्ता ने कहा, "ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। हमने बांग्लादेश की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाई है।" बांग्लादेश में बिजली की कमी और औद्योगिक विकास की जरूरतों के कारण यह आपूर्ति महत्वपूर्ण है। गोड्डा प्लांट की कुल क्षमता 1,600 MW है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश को जाता है।

हालांकि भारत-बांग्लादेश संबंधों में हाल के महीनों में तनाव बढ़ा है, विशेष रूप से सीमा विवाद और व्यापार मुद्दों पर, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बरकरार है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति का हिस्सा है, जो कूटनीतिक मतभेदों के बावजूद क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता देती है।

अडानी पावर का यह कदम भारत की ऊर्जा डिप्लोमेसी को मजबूत करता है। बांग्लादेश में बिजली की कमी से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो रहा है, और भारतीय आपूर्ति से वहां स्थिरता आई है। कंपनी ने कहा कि वह भविष्य में और विस्तार की योजना बना रही है। यह सहयोग दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का माध्यम भी बन सकता है।

MP Business Network Summit 2026: BNI Bhopal Hosts Power-Packed Platform for Growth & Collaboration

Industry Leaders, Policy Makers & Entrepreneurs Converge in Bhopal to Shape Madhya Pradesh's Economic Future: Strategic Partnerships & Investment Opportunities

Bhopal : The Madhya Pradesh Business Network Summit 2026, a landmark high-impact business convergence platform, kicked off today at Hotel Enrise by Sayaji in Bhopal. Presented by BNI Bhopal, the summit brings together entrepreneurs, MSMEs, corporates, investors, policymakers, startups, and leading business networks to foster collaboration, unlock investment opportunities, and drive sustainable economic growth in Madhya Pradesh.

Aligned with the national Vikshit Bharat Mission 2047 and the state's vision for Viksit Madhya Pradesh, the summit focuses on strengthening buyer-seller linkages, connecting local businesses with national and global networks, and building long-term ecosystem partnerships. The two-day event features eight curated discussion tracks covering high-potential sectors such as manufacturing, IT & digital economy, tourism, agri-processing, renewable energy, logistics, and infrastructure.

Key highlights include keynote addresses by senior industry and policy leaders, high-impact panel discussions on emerging opportunities, and the BNI Marketplace a structured platform for one-to-one business meetings based on the Givers Gain® philosophy of ethical, referral-based networking.The summit is curated by Mr. Pradeep Karambelkar, Executive Director of BNI Bhopal, an acclaimed ecosystem builder and strategic facilitator. It is supported by a strong organizing committee comprising senior business leaders from across the state.

This summit holds immense importance for Madhya Pradesh's growth journey. As the state accelerates its industrialisation drive through dedicated corridors, policy reforms, and investor-friendly initiatives, the event creates a powerful platform for strategic collaborations, joint ventures, high-value investment conversations, and access to key decision-makers. By bringing policy, capital, and enterprise together, the summit is expected to generate significant business deals, boost MSME growth, attract new investments, and contribute to the creation of a stronger, future-ready business ecosystem in Madhya Pradesh. The summit promises to deliver real, measurable outcomes for the state's economy.

Shapoorji Pallonji Group Plans to Raise Up to $2.5 Billion to Refinance Debt

SP Group Targets Lower-Cost Funding Amid High-Interest Burden; Move to Strengthen Balance Sheet and Support Construction & Infra Expansion

Mumbai: The Shapoorji Pallonji Group (SP Group), one of India's oldest and largest construction conglomerates, is actively working to raise up to $2.5 billion (approximately ₹21,000 crore) through a mix of debt and equity instruments to refinance its existing high-cost borrowings. The move comes as the group seeks to reduce its overall debt burden, lower interest expenses, and improve liquidity to support ongoing and new infrastructure projects.

SP Group is in discussions with global and domestic investors for a combination of long-term bonds, ECBs (external commercial borrowings), and potential strategic equity infusions. The fundraising is expected to be completed in phases over the next 12–18 months. The group, which owns major listed entities like Shapoorji Pallonji Engineering & Construction (SP E&C), Afcons Infrastructure, and a significant stake in Tata Sons, has been actively deleveraging since 2023.

The proceeds will primarily be used to prepay high-interest loans and fund capex in its core construction, engineering, and real estate businesses. The group has been facing elevated borrowing costs due to legacy debt from past expansions. Refinancing at lower rates is expected to improve cash flows and credit ratings.

SP Group Chairman Pallonji Mistry's family office and key entities have been in talks with global banks and private credit funds. The group also plans to monetise select non-core assets to reduce leverage further.

The announcement comes at a time when India's infrastructure sector is witnessing massive growth, with government capex and private investments driving demand for EPC players. SP Group's construction arm has a strong order book exceeding Rs 1.2 lakh crore.

Shares of group companies, including Afcons (post-listing) and associated stocks, traded flat amid broader market caution. Analysts view the refinancing as a positive step toward long-term financial stability and growth acceleration.

India-EU FTA to Level Playing Field for Textile Exporters: Govt

Tariff Cuts to Boost Competitiveness Against Bangladesh, Vietnam; Expected to Add $2-3 Bn in Annual Exports

New Delhi: The Indian government has said the proposed Free Trade Agreement (FTA) with the European Union will correct the long-standing tariff disadvantage faced by Indian textile exporters, giving them a fair chance to compete against low-cost rivals like Bangladesh, Vietnam, and Turkey.

In a statement issued by the Ministry of Commerce and Industry, officials highlighted that Indian textiles currently face average tariffs of 9-12% in the EU, while competitors from Bangladesh and Vietnam enjoy near-zero or very low duties under their respective FTAs or preferential schemes. The India-EU FTA, once finalised, is expected to eliminate or sharply reduce these tariffs on key categories such as apparel, home textiles, and technical textiles.

"Indian exporters have been at a structural disadvantage for years. The FTA will bridge this gap and enable our industry to regain lost market share in Europe," a senior commerce ministry official said. The EU is India's second-largest textile export destination after the US, with exports valued at around $8.5 billion in 2025. Industry estimates suggest the tariff correction could add $2-3 billion annually to textile exports within 3-5 years of implementation.

The textile sector, which employs over 45 million people and contributes 7% to GDP, has been pushing for duty parity in ongoing FTA negotiations. The government also noted that the agreement will include strong rules of origin, labour, and environmental standards, ensuring sustainable growth.

Textile industry bodies like CITI and AEPC welcomed the move, saying it would help reverse the decline in EU market share from 8% a decade ago to under 5% now. With India targeting $100 billion textile exports by 2030, the FTA is seen as a critical step toward reclaiming competitiveness in one of the world's largest consumer markets.

Adani Energy Solutions Secures Hybrid Power Mandate from Asahi India Glass

Long-Term PPA for Solar-Wind Hybrid Supply; Supports Asahi's Sustainability Goals and India's Renewable Energy Push

Mumbai: Adani Energy Solutions Limited (AESL), the power transmission and distribution arm of the Adani Group, has secured a major hybrid power supply mandate from Asahi India Glass Ltd (AIS), one of India's leading automotive and architectural glass manufacturers. The long-term power purchase agreement (PPA) will deliver renewable energy through a solar-wind hybrid project, marking another significant step in AESL's growing portfolio of corporate green power deals. Under the agreement, AESL will supply 100% renewable power to AIS's key manufacturing facilities in northern India. The hybrid setup combines solar and wind generation to ensure round-the-clock availability, addressing the intermittency challenges of standalone renewables. The project is expected to offset over 1.2 lakh tonnes of CO2 emissions annually, aligning with AIS's commitment to net-zero operations by 2040.

This partnership demonstrates how Indian corporates are increasingly adopting clean energy to meet ESG targets while ensuring energy security and cost predictability, said an AESL spokesperson. The deal strengthens AESL's position as a preferred renewable energy partner for large industrial consumers, following similar PPAs with companies in cement, steel, and textile sectors.

AIS, with plants in Rewari, Roorkee, and Taloja, consumes substantial power for its energy-intensive glass production. The hybrid supply will help reduce its carbon footprint and hedge against volatile grid tariffs.Analysts see this as part of India's accelerating corporate renewable procurement trend, driven by falling solar and wind tariffs and regulatory pressure on emissions. AESL, with over 20 GW of renewable PPAs signed, is rapidly scaling its renewable energy supply business.

As India targets 500 GW of non-fossil capacity by 2030, such industry tie-ups are critical for achieving renewable integration and industrial decarbonisation.

Hindalco to Double Odisha Smelter Capacity in Major Growth Push

Rs 15,000 Cr Expansion at Aditya Aluminium to Lift Capacity to 1 million Tonnes; Targets Higher Value-Added Products and Global Competitiveness

Bhubaneswar: Hindalco Industries Ltd, India's largest aluminium producer, has announced plans to double the smelting capacity at its Aditya Aluminium plant in Odisha's Lapanga as part of an aggressive growth strategy. The expansion, involving an investment of around Rs 15,000 crore, will increase the plant's smelting capacity from 360,000 tonnes per annum (TPA) to over 720,000 TPA, making it one of the largest single-location aluminium smelters in the world.

The project includes adding new potlines, upgrading power infrastructure, and enhancing downstream facilities for value-added products like rolled products, extrusions, and high-purity aluminium. The company aims to complete the expansion by 2028–29, leveraging Odisha's rich bauxite reserves and access to captive coal and power.

"This expansion strengthens our cost leadership and positions us to meet rising domestic demand while capturing export opportunities," said Satish Pai, Managing Director, Hindalco Industries. The company plans to increase its share of value-added products from the current 55% to over 70%, focusing on automotive, packaging, and aerospace sectors.

The move comes as India's aluminium demand is projected to grow 8–10% annually, driven by infrastructure, electric vehicles, and packaging industries. Hindalco's Odisha operations already benefit from low-cost power and proximity to ports, giving it a competitive edge over global peers.

Analysts expect the expansion to add Rs 8,000–10,000 crore to annual revenue by FY30, with EBITDA margins improving due to higher value-added output. The project will create over 5,000 direct and indirect jobs and support Odisha's industrialisation drive.

As India targets 5 million tonnes of aluminium production by 2030, Hindalco's Odisha expansion reinforces its leadership in the sector and contributes to national self-reliance in critical metals.

यूरोपीय देशों ने हवा से बिजली पर नया वादा: 100 GW विंड पावर का लक्ष्य

2030 तक 100 GW अतिरिक्त विंड क्षमता, जलवायु लक्ष्यों को गति; नॉर्थ सी में बड़े प्रोजेक्ट्स, भारत के लिए भी सबक

ब्रसेल्स: यूरोपीय संघ के प्रमुख देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नया बड़ा वादा किया है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, 2030 तक 100 गीगावाट (GW) अतिरिक्त विंड पावर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रतिबद्धता नॉर्थ सी कंट्रीज (नीदरलैंड्स, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूके) और अन्य EU सदस्य देशों ने संयुक्त रूप से की है।

यह लक्ष्य वर्तमान 200 GW विंड क्षमता को 300 GW तक ले जाएगा, जो EU की कुल बिजली मांग का 20% से अधिक पूरा करेगा। नॉर्थ सी में 300 GW से अधिक की संभावित विंड क्षमता का उपयोग करने के लिए बड़े ऑफशोर विंड फार्म्स बनाए जाएंगे। नीदरलैंड्स और डेनमार्क ने 2030 तक 20-25 GW ऑफशोर विंड का लक्ष्य रखा है, जबकि जर्मनी 30 GW का लक्ष्य रखता है।

यूरोपीय आयोग के ऊर्जा आयुक्त ने कहा, "विंड पावर यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो लक्ष्य का आधार है। यह प्रतिबद्धता रूस से गैस पर निर्भरता कम करेगी और हजारों रोजगार सृजित करेगी।" इस योजना से 2030 तक 5 लाख नई नौकरियां और 1,000 करोड़ यूरो का निवेश आने का अनुमान है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए भी यह सबक है, जहां विंड एनर्जी 2030 तक 140 GW लक्ष्य है। भारत में ऑफशोर विंड की संभावनाएं अपार हैं, लेकिन अभी केवल ऑनशोर पर फोकस है। यूरोप की यह प्रतिबद्धता वैश्विक हरित ऊर्जा परिवर्तन को नई गति देगी।

हिंदुस्तान कॉपर मध्य प्रदेश में तांबा ब्लॉक के लिए पसंदीदा बिडर बना

5,000 करोड़ से अधिक निवेश की योजना, 1.5 मिलियन टन सालाना उत्पादन लक्ष्य; राज्य की खनिज संपदा से आत्मनिर्भर भारत को बल

भोपाल : सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) मध्य प्रदेश के एक प्रमुख तांबा ब्लॉक के लिए पसंदीदा बिडर घोषित की गई है। कंपनी ने केंद्र सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा आयोजित नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाई, जिसके बाद उसे यह ब्लॉक आवंटित किया गया। यह मध्य प्रदेश में पिछले दस वर्षों में सबसे बड़ा तांबा खनन प्रोजेक्ट माना जा रहा है।

HCL के चेयरमैन और एमडी संजय कुमार ने कहा, यह हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इस ब्लॉक से 1.5 मिलियन टन सालाना तांबा अयस्क निकालने की योजना बना रहे हैं। इसमें 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा, जो 5-7 वर्षों में पूरा होगा। ब्लॉक में उच्च ग्रेड तांबा अयस्क होने का अनुमान है, जो भारत की बढ़ती तांबा मांग को पूरा करने में मदद करेगा।

भारत में तांबा की 90% से अधिक जरूरत आयात से पूरी होती है। यह खोज देश को तांबा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। मध्य प्रदेश सरकार ने कंपनी को लैंड, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई और कहा कि यह निवेश राज्य में हजारों रोजगार सृजित करेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट भारत के 2030 तक 1 मिलियन टन तांबा उत्पादन के लक्ष्य को गति देगा। HCL की अन्य इकाइयों (मलांजखंड, खेतड़ी) से उत्पादन बढ़ाने की योजना है। यह सफलता 'आत्मनिर्भर भारत' और खनिज आत्मनिर्भरता के विजन को मजबूत करती है।

MPBIL/2013/49052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट एवेनयुस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES
CALL FOR ARTICLES
Share Your Knowledge with
INVESTMENT AVENUES
We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:
1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in
write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

INVESTMENT AVENUES®
Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In BhopaL
Discover genuine real estate and well-assessed business opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.
Secure Deals. Smart Investments.
EMAIL: INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM
CONTACT: +91 73899 26586

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	25321	26062	25758	25540	25236	25018	24714	24496
BANK NIFTY	59610	62332	61195	60403	59266	58474	57337	56545
SENSEX	82270	84533	83611	82940	82018	81347	80425	79754
FINNIFTY	27331	28561	28061	27696	27196	26831	26331	25966
MIDCAP	13400	14122	13792	13596	13266	13070	12740	12544
ACC	1642	1756	1727	1685	1656	1614	1585	1543
AXISBANK	1366	1489	1433	1400	1344	1311	1255	1222
ABCAPITAL	341	370	362	351	343	332	324	313
BHARTIARTL	1969	2083	2043	2006	1966	1929	1889	1852
BHEL	263	294	279	271	256	248	233	225
BEL	367	386	379	373	366	360	353	347
BIOCON	449	513	486	467	440	421	394	375
CDSL	1320	1416	1387	1354	1325	1292	1263	1230
DATAPATTERN	2660	3537	3150	2905	2518	2273	1886	1641
ESCORTS	3364	3789	3668	3516	3395	3243	3122	2970
EICHERMOTOR	7130	7574	7374	7252	7052	6930	6730	6608
FEDERAL BANK	287	303	296	292	285	281	274	270
GRINFRAPOJECT	980	1138	1074	1027	963	916	852	805
HDFCBANK	929	981	961	945	925	909	889	873
HCLTECH	1691	1772	1753	1722	1703	1672	1653	1622
HINDUNILVR	2365	2527	2474	2419	2366	2311	2258	2203
HAL	4616	5163	4917	4766	4520	4369	4123	3972
HYUNDAI	2176	2402	2332	2254	2184	2106	2036	1958
IOC	163	176	170	167	161	158	152	149
ICICIBANK	1356	1445	1417	1386	1358	1327	1299	1268
INFY	1641	1752	1720	1681	1649	1610	1578	1539
ITC	322	335	330	326	321	317	312	308
KOTAKBNK	408	429	422	415	408	401	394	387
LICHOUSING	527	563	546	536	519	509	492	482
LT	3935	4238	4100	4017	3879	3796	3658	3575
LUPIN	2147	2261	2214	2181	2134	2101	2054	2021
MARUTI	14580	16264	15816	15198	14750	14132	13684	13066
M&M	3432	3706	3591	3512	3397	3318	3203	3124
MGL	1049	1133	1104	1077	1048	1021	992	965
MAZGAONDOC	2574	2981	2783	2679	2481	2377	2179	2075
PFC	379	428	410	394	376	360	342	326
RECLTD	364	406	395	380	369	354	343	328
RELIANCE	1397	1457	1434	1415	1392	1373	1350	1331
SBIN	1078	1149	1115	1097	1063	1045	1011	993
SUNPHARMA	1595	1715	1686	1641	1612	1567	1538	1493
SHRIRAMFINANCE	1020	1082	1055	1038	1011	994	967	950
TITAN	3979	4257	4147	4063	3953	3869	3759	3675
TCS	3127	3302	3254	3190	3142	3078	3030	2966
TATAMOTORS	349	373	363	356	346	339	329	322
UPL	702	745	735	719	709	693	683	667
VALIENT	245	273	261	253	241	233	221	213
WIPRO	236	250	245	241	236	232	227	223

गुलफूड 2026 में आठ भारतीय स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे: सरकार का चयन, उच्च संभावना वाले स्टार्टअप्स को मिलेगा वैश्विक मंच

फूड टेक, प्रोसेस्ड फूड और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में मजबूत, दुबई में वैश्विक खरीदारों से जुड़ेंगे; निर्यात बढ़ाने और ब्रांडिंग का बड़ा अवसर

नई दिल्ली: भारत सरकार ने आगामी गुलफूड 2026 (Gulfood 2026) में आठ उच्च संभावना वाले भारतीय स्टार्टअप्स को भाग लेने का चयन किया है। यह विश्व का सबसे बड़ा फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो है, जो 19-23 फरवरी 2026 को दुबई में आयोजित होगा। वाणिज्य मंत्रालय और APEDA ने इन स्टार्टअप्स को चुना है, जो फूड टेक, प्रोसेस्ड फूड, हेल्थ फूड और इनोवेटिव पैकेजिंग में मजबूत हैं।

ये स्टार्टअप्स भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनमें से कई स्टार्टअप्स पहले ही दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में निर्यात कर रहे हैं, लेकिन गुलफूड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से उन्हें बड़े खरीदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स से जुड़ने का मौका मिलेगा। सरकार का लक्ष्य इन स्टार्टअप्स के माध्यम से भारत के फूड प्रोसेसिंग निर्यात को और बढ़ाना है।

वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ये स्टार्टअप्स भारत की फूड इनोवेशन क्षमता को दर्शाते हैं। गुलफूड में उनकी भागीदारी से नए बाजार खुलेंगे और निर्यात में वृद्धि होगी। ये स्टार्टअप्स हेल्दी स्नैक्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, रेडी-टू-ईट फूड और सस्टेनेबल पैकेजिंग में विशेषज्ञता रखते हैं।

गुलफूड 2026 में 5,000 से अधिक प्रदर्शक और 1 लाख से अधिक विजिटर्स की उम्मीद है। भारत का पवेलियन इस बार सबसे बड़ा होगा, जिसमें 200 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन स्टार्टअप्स की सफलता से भारत का फूड प्रोसेसिंग निर्यात 2026-27 में 10% से अधिक बढ़ सकता है। यह कदम 'मेक इन इंडिया' और 'विकसित भारत' के विजन को मजबूत करेगा।

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in